

उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान का मूल्यांकन

नीरज कुमार राय

सहायक प्रोफेसर

राजकीय महिला महाविद्यालय

ढिँढई, पट्टी, प्रतापगढ़

सारांश : मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत नवरात्र के दौरान की गयी थी सरकार के मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा सम्मान और सशक्तिकरण के लिए सक्रीय नियम-कानून तैयार करना है उत्तर प्रदेश में हाथरस और बलरामपुर में घटित बलात्कार की घटनाओं ने राज्य सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए थे इसी बीच मुख्यमंत्री ने 17 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति अभियान को शुरू किया था प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है और मिशन शक्ति अभियान का मूल्यांकन करता है

मुख्य शब्द : मिशन शक्ति अभियान, अपराध, सुरक्षा, सम्मान, सशक्तिकरण, वन स्टाप सेंटर

एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध के मामले में 2019 में देश का कुल औसत 62.4 फीसदी दर्ज किया गया. जबकि उत्तर प्रदेश में महिला के प्रति अपराध 55.2 प्रतिशत रहा. वहीं 2019 में मिजोरम में महिलाओं के प्रति अपराध का औसत 88.3, मणिपुर में 58.0, मेघालय में 57.3, राजस्थान में 110.4 और केरल जैसे छोटे राज्य में यह औसत 62.7 रहा. यूपी में महिलाओं के प्रति अपराध का औसत वर्ष 2016 में 52.6, वर्ष 2017 में 66.4 और 2018 में ग्राफ गिरकर 60.3 रहा जो कि अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम है. एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार महिलाओं के प्रति अपराध पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने कड़ी मशकत की है. पुलिस और न्याय प्रक्रिया को दुरुस्त करने के साथ ही महिलाओं के गुनाहगारों को जेल भेजने का रास्ता भी तैयार किया. वर्ष 2016 में यूपी में दुष्कर्म के 3289 मामले दर्ज किए गए थे जबकि 2020 में यह आंकड़ा 2232 पर आ गया. सपा सरकार के 2016 के मुकाबले योगी सरकार 2020 तक दुष्कर्म के मामलों में 32 फीसदी कमी लाने में सफल रही. प्रदेश में 2016 में महिला अपहरण के 11121 मामले थे वहीं 2020 तक योगी सरकार ने 27 फीसदी अपहरण के मामलों में कमी लाते हुए इसे 11057 पर रोक दिया. आंकड़ों के मुताबिक अखिलेश सरकार के दौरान 2013 में 2593, 2014 में 2990 और 2015 में 2662 महिलाएं दुष्कर्म का शिकार हुईं. साइबर अपराध के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं. प्रदेश में 18 साइबर थाने खोल दिए गए हैं लेकिन फिर भी रोज घट रहे नए-नए तरह के अपराध से लोग लगातार जालसाजी का शिकार हो रहे हैं. उत्तर प्रदेश में महिलाएं साइबर क्राइम का सबसे ज्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिकार हो रही है. वहीं महिलाओं के खिलाफ ज्यादातर साइबर अपराध उनके परिचित द्वारा किए जा रहे हैं. वहीं महिलाओं को साइबर अपराध से बचाने के लिए प्रभावी कानून भी उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है. बीते साल 2020 में 136 साइबर अपराध की शिकार महिलाओं के मामले राज्य महिला आयोग ने दर्ज किए गए हैं. वहीं महिला आयोग के द्वारा पीड़ित महिलाओं को साइबर क्राइम सेल की मदद से मदद की जा रही है. राज्य महिला आयोग के पास जहां महिला उत्पीड़न से संबंधित हर तरह की शिकायतें पहुंचती हैं तो वहीं बीते साल 2020 में साइबर अपराध की शिकार महिलाओं की शिकायतें भी खूब पहुंची. साइबर अपराध की शिकार ज्यादातर महिलाएं थाने में शिकायत न करके सीधे राज्य महिला आयोग में शिकायत करती हैं. क्योंकि उनके साथ ज्यादातर मामले उनके अपने परिचित या प्रेमियों के द्वारा उन्हें बदनाम करने और अश्लील वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल करने के हैं. बीते साल में कुल 136 साइबर अपराध की शिकार महिला आयोग के पास सामने आई है. वहीं आयोग के द्वारा इन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए भी पुलिस की मदद ली जा रही है राज्य महिला आयोग के पास पहुंचे मामलों में सबसे ज्यादा साइबरस्टॉकिंग के मामले हैं. इस तरह के अपराध में ऑनलाइन उत्पीड़न और ऑनलाइन दुरुपयोग के लिए किसी को परेशान

करने के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है. इस तरह के अपराध में पीड़ित महिला को सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम करने की कोशिश होती है. इस तरह के साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी जैसे किसी महिला की फेसबुक और ईमेल का नाम पासवर्ड प्राप्त करके उसकी व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग करना होता है. इस तरह के मामले भी महिला आयोग के पास पहुंचे हैं.

उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान सरकार द्वारा महिलाओं सुरक्षा सम्मान और सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है. इस अभियान के अंतर्गत राज्य में महिलाओं व बालिकाओं के लिए विशेष प्रयास और नियम कानून तैयार किये गए हैं. प्रदेश के समस्त 75 जनपदों 521 ब्लॉकों 59,000 पंचायतों 630 शहरी निकायों और 1,535 थानों के माध्यम से अप्रैल 2021 तक मिशन मोड में चलाया गया है. साथ ही महिला पीड़िता के लिए थाने में अलग कमरों में महिला पुलिस कर्मियों द्वारा शिकायत पंजीकरण किया गया.

- मिशन शक्ति की सक्रियता और उत्तर प्रदेश पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही की वजह से अब तक कुल 3500 से भी जादा अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है.
- अभियान की शुरुआत से 24 मार्च 2021 के बीच 12 आरोपितों को फांसी की सजा और 456 को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है.
- उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में विशेष सुविधा मिलेगी.
- महिलाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने के लिए महिला शक्ति मिशन के अंतर्गत जगह जगह शिविर लगाकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.
- मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी स्कूल कालेजों में मिशन शक्ति कार्यक्रम को सक्रियता से पहुँचाने का आदेश दिया है.
- उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में विशेष सुविधा मिलेगी.
- महिला शक्ति मिशन उत्तर प्रदेश की महिलाओं और बालिकाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया है.
- इस अभियान के तहत हर महीने एक-एक सप्ताह के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जायेगा.
- महिला पुलिस कर्मियों की टीम सभी थानों में मौजूद होगी.
- महिलाओं की शिकायतें महिला पुलिस ही सुनेंगी.
- मिशन शक्ति के तहत एंटी रोमिओ स्कायड यूपी पुलिस 112 और महिला हेल्प लाइन 1090 को कारवाही करने का अधिकार होगा.
- मनचलों और अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही के साथ साथ उनका सामाजिक बहिष्कार और उनके पोटर चौराहों पर लगेंगे.

मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति को सफल बनाने के लिए कई घोषणाएं की हैं. मुख्यमंत्री ने पुलिस भर्ती में भी 20 फीसद महिलाओं की भर्ती की घोषणा की है. साथ ही महिला पीएसी की तीन कंपनियां भी इसी साल वजूद में आने की उम्मीद है. इससे महिला अपराध रोकने में मदद मिलेगी. महिलाओं को बराबरी का अधिकार प्रदान करने व उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हो रहे प्रयासों का असर भी इस साल दिखेगा. कन्या सुमंगला योजना का कवच : योगी सरकार कन्या भ्रूण हत्या रोकने बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को और बेहतर करने के लिए गरीब परिवारों में बेटी के पैदा होने पर कन्या सुमंगला योजना का कवच प्रदान करेगी. इस योजना में सरकार गरीब परिवारों को बालिका के जन्म होने पर तत्काल दो हजार रुपये प्रदान करती है. अलग-अलग समय पर बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पढ़ाई के लिए सरकार कुल 15 हजार रुपये का प्रवधान है. पिछले वर्ष यानी 2020 में 5.25 लाख परिवारों को ही योजना का लाभ दिया गया. किंतु वर्ष 2021 में करीब 20 लाख परिवारों को सरकार इस योजना का लाभ दिया जाएगा. मंडल मुख्यालयों पर बनेंगे वर्किंग वूमन हॉस्टल : उत्तर प्रदेश सरकार शहरों में अकेले रहकर

नौकरी-पेशा करने वाली महिलाओं को सुरक्षित आवास मुहैया कराने के लिए सभी मंडल मुख्यालयों पर वर्किंग वूमन हॉस्टल बनाने जा रही है। बड़े मंडल मुख्यालयों पर 100 बेड व छोटे मुख्यालयों पर 50 बेड के छात्रावास बनाए जाएंगे। यहां पर रहने के साथ ही खान-पान की भी अच्छी व्यवस्था रहेगी। यह छात्रावास उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम एनजीओ के माध्यम से संचालित करेगी। इसके लिए इसी साल टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ से भी बढ़ेगी जागरूकता : इस योजना के तहत मुजफ्फरनगर में शुरू किए गए ग्राम स्तरीय जन जागरूकता अभियान का ऐसा असर पड़ा कि 13 गांवों में घर के बाहर बेटियों के नाम की नेम प्लेट लगनी शुरू हो गई है। यानी यहां के लोग इस कोशिश में जुटे हैं कि उनका घर बेटियों के नाम से जाना जाए। प्रदेश सरकार इस योजना को 2021 में कई और जिलों में शुरू करेगी। बालिका सुरक्षा जागरूकता अभियान से सुरक्षित होंगी बेटियां : बालिका सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत चरणबद्ध तरीके से विद्यालयों में ऐसे सत्रों का आयोजन किया जाता है ताकि बालिकाएं सुरक्षित-असुरक्षित स्पर्श, महिला झूठसा व शोषण से बचाव कर सकें। उन्हें विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। यह अभियान भी वर्ष 2021 में पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाएंगे वन स्टाप सेंटर : सरकार ने हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सभी प्रकार की आवश्यक सेवाओं जैसे मुसीबत के समय अल्प प्रवास, चिकित्सीय सहायता, परामर्शी सेवाएं, विधिक सहायता एवं पुलिस सहायता एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए वन स्टाप सेंटर सभी जिलों में स्थापित किए हैं। इसमें जरूरी स्टाफ की भी सरकार ने नियुक्ति कर दी है। आपात परिस्थितियों में इमरजेंसी रिस्पांस एवं रेस्क्यू सेवाएं पुलिस विभाग की डायल 112, स्वास्थ्य विभाग की 108 व 102 एंबुलेंस सेवाओं से की जाएगी। वन स्टाप सेंटर भी सभी 75 जिलों में अपने-अपने भवन में शुरू हो जाएंगे। यह केंद्र महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग का दावा है कि प्रदेश की 6 करोड़ से अधिक महिलाओं को जागरूक किया जा चुका है। महिलाओं और बालिकाओं के प्रति लोगों की सोच में बदलाव देखने को मिल रहा है। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए सरकार की योजनाओं और मिशन शक्ति अभियान से उनका मनोबल बढ़ रहा है। प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान के तहत शहरी व ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण का पाठ पढ़ाया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से प्रदेश की 6 करोड़ से अधिक महिलाओं को अब तक जागरूक किया जा चुका है। दावा किया गया है कि आधी आबादी को सशक्त बनाने के सरकारी प्रयास जमीनी स्तर पर रंग ला रहे हैं। प्रदेश की महिलाओं व बेटियों को इस अभियान से न सिर्फ सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल रही है बल्कि उन्हें इन योजनाओं का लाभ भी सीधे तौर पर मिल रहा है। बेटियों को सम्मान दिलाने व शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए तत्पर योगी सरकार के मिशन शक्ति अभियान के तहत फरवरी माह में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पहली बार महिलाओं व बेटियों के लिए शुरू किए गए इस वृहद अभियान से उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है।

सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं की टीमों द्वारा ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को रोजगार से जुड़े नए अवसरों की जानकारी दी जा रही है। जिसके तहत उनको लघु व कुटीर उद्योग, जैविक खेती, मास्क बनाने संग ड्रेस व डिजाइनर ज्वेलरी से जुड़े कामों को सिखाया जा रहा है। महिलाएं भी उत्साह संग इन कार्यों को सीख रही हैं। अभियान के तहत विभाग की ओर से महिलाओं व बेटियों को स्वावलंबी बनाने के कार्य पर बल दिया जा रहा है। मिशन शक्ति के अंतर्गत समस्त कल्याणकारी तथा संरक्षण संबंधी योजनाओं को उत्तर प्रदेश की अंतिम महिला तक पहुंचाने हेतु महिला कल्याण विभाग प्रतिबद्ध है। इस मिशन के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं के प्रति लोगों की सोच में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। यूपी में मिशन शक्ति के तहत उच्च शिक्षा में नौ दिनों तक इस विशेष अभियान के तहत महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिसमें प्रदेश के 6,349 कॉलेजों के 5,57,383 छात्र छात्राओं और 1,46,177 शिक्षकों ने मिशन शक्ति के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन से जुड़ी शपथ ली। मार्शल आर्ट की ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यशाला में 3007 कॉलेजों की 4,46,355 छात्राओं को प्रशिक्षित किया गया। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 6,349 कॉलेजों के 5,57,383 छात्र-छात्राओं को वेबिनार, जागरूकता कार्यक्रम और प्रतियोगिता के तहत जागरूक किया गया। निबंध, पोस्टर, स्लोगन और क्विज प्रतियोगिता में 2,57,407 छात्राओं ने हिस्सा लिया। शारीरिक स्वास्थ्य वर्धन व पोषण जागरूकता कार्यक्रम में 2,731 कॉलेजों के 2,42,036 छात्राओं और 14,364 शिक्षकों ने प्रतिभाग लिया। लैंगिक समानता, घरेलू हिंसा से सुरक्षा, पॉक्सो एक्ट, महिला हेल्पलाइन से जुड़ी वेबिनार में 2,986 कॉलेजों में 1,783 विषय विशेषज्ञों ने 3,13,996 छात्राओं को इन मुद्दों से जुड़ी जानकारी दी गई।

निष्कर्ष : सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रारंभ किया गया बेहद सफल अभियान है च इस अभियान से सरकार के सभी विभाग जमीनी स्तर पर कार्य करते दिखाई दिए च महिलाओं की उत्तर प्रदेश में स्थिति बेहद खराब थी एपूर्व मे उनको किसी प्रकार की जानकारी और सुविधा न प्रदान करना एसुरक्षा के उचित उपाय न करना और विविध कार्यों मे उनको सम्मान न देना एक तरह से उनकी गरिमा को गिराना था लेकिन मिशन शक्ति अभियान ने उनको आत्मिक मजबूती दी और उत्तर प्रदेश की महिलायें सभी कार्यों मे आगे दिखी चइस अभियान के द्वारा अपराधों को तीव्र गति से कम किया गया च उनको व्यवसाय एरोजगार एनौकरी एशिक्षा आदि मे सशक्त किया गया च उन्हे उत्साहित कर उनके सपनों को उड़ान दी गईं

सन्दर्भ :

- 1 <https://www.aajtak.in/crime/police-and-intelligence/story/up-bjp-yogi-sarkar-4-years-ncrb-statistics-denial-claim-crime-less-police-crime-1223822-2021-03-17>
- 2 <https://www.etvbharat.com/hindi/uttar-pradesh/state/lucknow/cyber-crime-is-increasing-with-women-in-up/up20210112104623776>
- 3 <https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/story-up-government-initiative-on-mission-shakti-abhiyan-know-what-is-the-plan-of-cm-yogi-3882027.html>
- 4 <https://indiascheme.com/mission-shakti-yojana/>
- 5 <https://hindi.news18.com/news/uttar-pradesh/lucknow-more-than-6-crore-women-aware-under-mission-shakti-in-uttar-pradesh-upas-3463001.html>
- 6 <https://www.aajtak.in/india-today-plus/rajya/story/mission-shakti-campaign-of-up-action-on-25-criminals-everyday-1218089-2021-03-06>